भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1910

जिसका उत्तर 14.12.2023 को दिया जाना है

भारतमाला परियोजना

1910 श्री एस.वेंकटेशन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतमाला परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं की संशोधित लागत कितनी है;

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यमों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक माध्यम का अनुपात क्या है;

(ग) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान इसके लिए वित्त में वृद्धि करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का हिस्सा कितना है;

(घ) क्या वर्ष 2024 तक एलआईसी का योगदान 1.24 लाख करोड़ रूपए हो जाएगा; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एलाआईसी की निधियों का उपयोग किन-किन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा मूल्यांकन के अनुसार भारतमाला परियोजना चरण- I की संशोधित लागत 10.95 लाख करोड़ है ।

(ख) राजमार्गों के विकास के लिए निधि सरकार द्वारा बजटीय आवंटन और आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के तहत उधार लेने के लिए एनएचएआई को मंजूरी के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से संसाधन जुटाता है। पिछले 5 वर्षों में उधार का वर्षवार विवरण संलग्न है ।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान एलआईसी से 10,309 करोड़ रूपएं उधार लिए गए ।

(घ) और (ड.) एनएचएआई द्वारा निधि उधार लेना बंद कर दिया गया है ।

अनुबंध

भारतमाला परियोजना के संबंध में श्री एस वेंकटेशन द्वारा पूछे गए दिनांक**14.12.2023** के **लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1910 के भाग (**ख**) के उत्तर में उल्लिखित** अनुबंध

पिछले 5 वर्षों के दौरान लिए गए उधार का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**राशि (मूल राशि)**
2018-19	61,217
2019-20	74,987
2020-21	65,080
2021-22	76,150
2022-23	798*

* एनएचएआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में 54ईसी बांड के माध्यम से केवल 798 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 के बाद के लिए कोई आईईबीआर नहीं है।

*****